

उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास विभाग,

देहरादून।

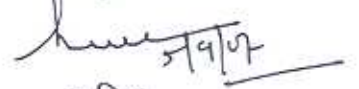
पत्रांक 1417 / आठ-संशोधन / पी.1-03(नैनीताल) / यू.आर.आर.डी.ए. / 2007-08 दिनांक 07 सितम्बर, 2007

: शुद्धि पत्र :

जिला नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घोडाखाल-धुलई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम महारागौव परगना छः खाता में प्रस्तावित जारी धारा 4/17 एवं धारा 6/17 की क्रमशः विज्ञप्ति संख्या 916/पी.1-03(नैनीताल)/यू.आर.आर.डी.ए./2006-07, दिनांक 22 जून, 2006 एवं संख्या 897/पी.1-03(नैनीताल)/यू.आर.आर.डी.ए./2007-08, दिनांक 21 जून, 2007 जो राजकीय गजट में क्रमशः दिनांक 22 जून, 2006 एवं 21 जून, 2007 को प्रकाशित हुई है, को निम्न प्रकार संशोधित समझा जाए :-

1. गाटा सं. 285 में अर्जित रकबा 0.20 हे० के स्थान पर 0.005 हे० पढ़ा जाए।
2. गाटा सं. 2438 में अर्जित रकबा 0.019 हे० के स्थान पर 0.015 हे० पढ़ा जाए।
3. गाटा सं. 2802 में अर्जित रकबा 0.039 हे० के स्थान पर 0.015 हे० पढ़ा जाए।
4. गाटा सं. 2879ब में अर्जित रकबा 0.08 हे० के स्थान पर गाटा संख्या 2879अ रकबा 0.08 हे० पढ़ा जाए।
5. गाटा सं. 2994 अ में अर्जित रकबा 0.04 हे० के स्थान पर 0.03 हे० पढ़ा जाए।
6. गाटा सं. 3049 में अर्जित रकबा 0.040 हे० के स्थान पर 0.011 पढ़ा जाए।
7. ग्राम के गाटा संख्याओं में अर्जित कुल रकबा 1.193 हे० के स्थान पर 0.931 हे० पढ़ा जाए।

आज्ञा से

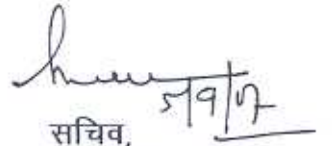


सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना सम्बन्धी शुद्धि पत्र का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में कराने तथा इसकी 5-5 प्रतियाँ जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. सूचना निदेशक, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना का प्रकाशन जनपद नैनीताल को दो प्रमुख समाचार पत्रों में शीघ्र कराने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, नैनीताल।
7. अधीक्षण अभियन्ता, पी.आई.यू. (पी.एम.जी.एस.वाई.) एवं लो.नि.वि., नैनीताल।
8. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।



सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग।